



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

Ms.  
21/11/99

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417 ]  
No. 417]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 1999/आषाढ़ 16, 1921  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 1999/ASADHA 16, 1921

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

( विधायी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1999

का.आ. 548( अ ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

श्री उदयभान सिंह कुशवाहा, भूतपूर्व विधायक ने, 10-3-99 को यह अभिकथन करते हुए एक याचिका फाइल की थी कि मध्य प्रदेश में 2-भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित संसद् ( बारहवीं लोक सभा ) के आसीन सदस्य डा. राम लखन सिंह कुशवाहा ने, तारीख 28-9-1998 को अपने निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से अपना नाम हटवा लेने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(घ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन निरर्हता उपगत की थी;

और, भारत के राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन उक्त याचिका के संदर्भ में, निर्वाचन आयोग की राय मांगी थी;

और, निर्वाचन आयोग की यह राय है (उपाबंध देखिए) कि उक्त याचिका का अब कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि वह 26 अप्रैल, 1999 को बारहवीं लोक सभा के विघटन पर निष्फल हो गई है।

अतः, अब, मैं, के. आर. नारायणन, भारत का राष्ट्रपति, श्री उदयभान सिंह कुशवाहा को पूर्वोक्त याचिका खारिज करता हूँ।

जून, 28 1999

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच. 11026/2/99-वि. II]

रघबीर सिंह, सचिव

उपाबंध

### भारत निर्वाचन आयोग

#### गणपूर्ति

माननीय श्री जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति  
निर्वाचन आयुक्त

माननीय डा. एम. एस. गिल  
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

माननीय श्री जे. एम. लिंगडोह  
निर्वाचन आयुक्त

### 1999 का निर्देश मामला संख्यांक 2

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

संदर्भ: लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य, डा. राम लखन सिंह कुशवाहा की अभिकथित निरर्हता।

#### राय

संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त तारीख 16-3-1999 के इस निर्देश में, इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि संसद् (बारहवीं लोक सभा) के तत्कालीन आसीन सदस्य, डा. रामलखन सिंह कुशवाहा, संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं अथवा नहीं।

- उपर्युक्त प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भिंड के भूतपूर्व विधायक श्री उदयभान सिंह कुशवाहा द्वारा तारीख 10-3-1999 को भारत के राष्ट्रपति को दी गई एक याचिका से उद्भूत हुआ। याची ने, यह अभिकथन किया कि डा. रामलखन सिंह कुशवाहा, जो फरवरी-मार्च, 1998 में हुए बारहवीं लोक सभा के साधारण निर्वाचन में मध्य प्रदेश के 2-भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, ने अपना नाम तारीख 28-9-1998 को 12-भिंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (जो उक्त भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत था) की नामावली से हटवा लिया था। याची ने यह तर्क दिया कि डा. रामलखन सिंह कुशवाहा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का अपना अधिकार खो देने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(घ) के अधीन निर्वाचक होने की कानूनी अपेक्षाओं को पूरा न करने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(घ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ड.) के अधीन बारहवीं लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए थे।

3. श्री उदयभान सिंह कुशवाहा की याचिका पर, राष्ट्रपति को अपनी राय देने के पूर्व, आयोग ने मामले की जाँच करने का विनिश्चय किया। तदनुसार, आयोग ने, अपनी 5 अप्रैल, 1999 की सूचना द्वारा याची को राष्ट्रपति को अपनी पूर्वोक्त याचिका में अंतर्विष्ट अभिकथनों की बाबत शपथपत्र द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित और सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ 14 मई, 1999 को या उससे पूर्व लिखित कथन फाइल करने के लिए कहा। तारीख 5 अप्रैल, 1999 की पूर्वोक्त सूचना के अनुसरण में, याची ने, आयोग के समक्ष तारीख 12 अप्रैल, 1999 को अपना लिखित कथन फाइल किया।
4. आयोग इस मामले पर आगे विचार करने वाला ही था कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हो गईं जिनका इस प्रक्रम पर आयोग के वर्तमान निर्देश को बनाए रखने पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। बारहवीं लोक सभा, जिसके डा. रामलखन सिंह कुशवाहा सदस्य थे, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड(2) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 26 अप्रैल, 1999 को अपने आदेश द्वारा विघटित कर दी थी। तारीख 26 अप्रैल, 1999 का उक्त राष्ट्रपतीय आदेश लोक सभा सचिवालय द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिए, तारीख 26 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं. 37/2/99टी द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित कर दिया गया है।
5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है श्री उदयभान सिंह कुशवाहा की याचिका में उठाया गया प्रश्न डा. राम लखन सिंह कुशवाहा की बारहवीं लोकसभा के सदस्य बने रहने में अभिकथित निरर्हता से संबंधित है। अब, राष्ट्रपति द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 1999 को बारहवीं लोक सभा विघटित कर दी गई है। इस प्रकार वह सदन ही अब अस्तित्व में नहीं रह गया है जिसकी सदस्यता के संबंध में, डा. रामलखन सिंह कुशवाहा की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया गया था।
6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को संबोधित श्री उदयभान सिंह कुशवाहा की तारीख 10.3.1999 की याचिका का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि वह तारीख 26 अप्रैल, 1999 को बारहवीं लोक सभा के विघटन पर निष्फल हो गई है।
7. तदनुसार, वर्तमान मामले में, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश आयोग की उपर्युक्त राय सहित लौटाया जा रहा है।

(जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति)  
निर्वाचन आयुक्त

(डा. एम.एस. गिल)  
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

(जे.एम. सिंगडोह)  
निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,  
तारीख : 21 मई, 1999

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1999

S.O. 548(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

O R D E R

Whereas, a petition dated 10.3.1999 was filed by Shri Udaybhan Singh Kushwaha, Ex-MLA, Bhind alleging that Dr. Ramlakhan Singh Kushwaha, a sitting Member of Parliament (Twelfth Lok Sabha), elected from 2-Bhind Parliamentary Constituency in Madhya Pradesh, had incurred disqualification under article 102(1)(e) of the Constitution of India, read with section 4(d) of the Representation of the People Act, 1951, for getting his name deleted from the electoral roll of his Constituency on 28.9.1998;

And whereas, the President of India had sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said petition;

And whereas, the Election Commission is of the opinion (vide Annexure) that the said petition does not survive any longer as the same has become infructuous on the dissolution of the Twelfth Lok Sabha on 26th April, 1999;

Now, therefore, I, K.R. Narayanan, President of India, do hereby dismiss the aforesaid petition of Shri Udaybhan Singh Kushwaha.

June 28, 1999

PRESIDENT OF INDIA

[F. No. H-11026 (2)/99-Leg. II]

RAGHBIR SINGH, Secy.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

ANNEXURE

**CORAM :**

Hon'ble Shri G.V.G.Krishnamurthy      Hon'ble Dr.M.S.Gill      Hon'ble Shri J.M.Lyngdoh  
Election Commissioner      Chief Election Commissioner      Election Commissioner

**Reference Case No. 2 of 1999**

[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India]

**In re:** Alleged disqualification of Dr. Ramlakhan Singh Kushwaha, a former Member of Lok Sabha.

**OPINION**

This is a reference dated 16.3.1999 from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103 (2) of the Constitution of India, on the question whether Dr. Ramlakhan Singh Kushwaha, a then sitting Member of Parliament (Twelfth Lok Sabha), had become subject to disqualification, for being a member of that House, under Article 102 (1) of the Constitution of India.

2.           The above question arose on a petition, dated 10.3.1999, made by Shri Udaybhan Singh Kushwaha, Ex-MLA, Bhind, to the President of India under Article 103 (1) of the Constitution. The petitioner alleged that Dr. Ramlakhan

Singh Kushwaha, who was elected from 2-Bhind Parliamentary Constituency in Madhya Pradesh at the Twelfth Lok Sabha General Election held in February-March, 1998, got his name deleted from the electoral roll for 12-Bhind Assembly Constituency (comprised within the said Bhind Parliamentary Constituency) on 28.9.1998. The petitioner contended that on forfeiting his right of exercising adult franchise and ceasing to fulfil the statutory requirement under section 4(d) of the Representation of the People Act, 1951, of being an elector, Dr. Ramlakhan Singh Kushwaha had become subject to disqualification for continuing as a member of the Twelfth Lok Sabha, under Article 102 (1) (e) of the Constitution of India read with Section 4 (d) of the Representation of the People Act, 1951.

3. Before tendering its opinion to the President, on the petition of Shri Udaybhan Singh Kushwaha, the Commission decided to make enquiry in the matter. Accordingly, the Commission, vide notice dated 5th April, 1999, called upon the petitioner to file a written statement, duly supported by an affidavit and accompanied by all relevant documents, on or before 14th May, 1999, in respect of the allegations contained in his aforesaid petition to the President. Pursuant to the aforesaid notice dated 5th April, 1999, the petitioner filed his written statement before the Commission on 12th April, 1999.

4. While the Commission was in the process of looking further into the matter, certain important developments have taken place which have vital bearing on the very maintainability of the present reference to the Commission, at this stage. The Twelfth Lok Sabha of which Dr. Ramlakhan Singh Kushwaha was a

member, was dissolved by the President by his Order dated 26th April, 1999, in exercise of the powers conferred on him by sub-clause (b) of clause (2) of Article 85 of the Constitution of India, The said Presidential order dated 26th April, 1999 has been published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-I, dated 26th April, 1999, by the Lok Sabha Secretariat, for general information vide Notification No.37/2/99/T, dated 26th April, 1999.

5. At stated above, the question raised in the petition of Shri Udaybhan Singh Kushwaha relates to the alleged disqualification of Dr. Ramlakhan Singh Kushwaha, for continuing as a member of the Twelfth Lok Sabha. The Twelfth Lok Sabha has now been dissolved by the President on 26th April, 1999. Thus, the very House, in relation to the membership whereof the question of alleged disqualification of Dr. Ramlakhan Singh Kushwaha was raised is no longer in existence now.

6. In view of the above, the petition, dated 10.3.1999 of Shri Udaybhan Singh Kushwaha, to the President of India under Article 103 (1) of the Constitution does not survive any longer, as the same has become infructuous on the dissolution of the Twelfth Lok Sabha on 26th April, 1999.

7. The reference received from the President, in the present case is, accordingly, returned with the opinion of the Election Commission to the above effect.

(G.V.G. Krishnamurty)  
Election Commissioner

(Dr. M.S. Gill)  
Chief Election Commissioner

(J.M. Lyngdoh)  
Election Commissioner

New Delhi.

Dated : 21st May, 1999.